ISSN 2348-3857

हैदराबाद रियासत का विलय और सरदार पटेल

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

बालूदान बारहठ

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत एक बड़ी भू-राजनीतिक समस्या से त्रस्त था। पाँच सौ से अधिक देशी रियासतों के बारे में औपनिवेशिक सरकार ने कहा कि वे अब इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अपना अधिमिलन भारत या पाकिस्तान, किसी भी देश के साथ करें। अधिकाधिक रियासतों का विलय भारत में हो यह जिम्मेदारी सरदार पटेल के पास थी, जिन्होंने वी.पी. मेनन को अपना सचिव बना यह कार्य कुशलतापूर्वक किया। कुछ रियासतों का विलय अत्यन्त चुनौतीपूर्ण था, जिसमें हैदराबाद भी एक थी। हैदराबाद पर मीर उसमान अली का शासन था जिसने भारत में विलय करने से इन्कार कर दिया जबकि रियासत की 80 प्रतिशत हिन्दु जनसंख्या भारत में विलय चाहती थी। उधर रियासत के मुसलमानों ने 'रजाकार' नामक संगठन की स्थापना कर हिन्दुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया। निजाम को प्रत्यक्ष, परोक्ष इंग्लैण्ड और पाकिस्तान की सहायता भी प्राप्त थी। इन सब कारणों से हैदराबाद की स्थिति विकट होती जा रही थी। सरदार पटेल ने अन्तिम विकल्प के रूप में सैन्य कार्यवाही का प्रस्ताव रखा लेकिन नेहरू इस पर बमुश्किल सहमत हुए। अन्ततः 13 सितम्बर, 1948 को 'ऑपरेशन पोलो' के नाम से सैन्य आक्रमण हुआ और 17 सितम्बर को निजाम ने समर्पण कर दिया। इसके साथ ही व औपनिवेशिक भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक का भारत में विलय हो गया।

संकेताक्षर : *स्वतन्त्र राज्य, रजाकार संगठन, ऑपरेशन पोलो, विलय*

प्राचीन काल से भारत न केवल सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से एक संगठित इकाई रहा है अपितु कई चक्रवर्ती सम्राटों के काल में भारत राजनीतिक रूप से भी एक रहा है। दार्शनिक चिन्तन में तो हिमाचल के दक्षिण से समुद्र के उत्तर तक का भाग सदियों से एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में बना रहा है। लेकिन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत एक ऐसी भू-राजनीतिक समस्या से त्रस्त था, जिसे इतिहास में शायद ही किसी देश ने झेला हो। क्योंकि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब वे अपने पीछे पाँच सौ से अधिक राजनीतिक टुकड़े छोड़ गए थे, जिन्हें छोटे-बड़े देशी राज्य, रजवाड़े, ठिकाने आदि कहते थे जो सामूहिक रूप से देशी रियासते कहलाती थी। देश के भूखण्ड़ का चालीस प्रतिशत भाग देशी रियासतों के अधीन था, जहाँ देश की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा निवासरत था। इन रियासतों का आकार, स्थिति, राजनीतिक हैसियत और आकांक्षाएँ अलग-अलग थी। एक तरफ कश्मीर और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें थी जो यूरोप के किसी देश के बराबर थी, वहीं दूसरी ओर ऐसी छोटी जागीरे भी थी, जिनमें दर्जन भर गाँव थे। कुछ रियासतें ऐसी थी, जिन्होंने 11वीं से 16वीं सदी तक मुस्लिम आक्रांताओं का बड़े साहस से सामना किया था तो कुछ ऐसी रियासतें भी थी जो स्वयं इन्हीं हमलावरों से ताल्लुक रखती थी। व्यापारियों की एक कम्पनी से शुरूआत करके पूरे देश पर वर्चस्व जमाने वाली ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए कई रियासतों ने सहायक की भूमिका निभाई थी तो दूसरी कई इस नवीन साम्राज्य की स्थापना को रोकने के प्रयास में अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर चुकी थी। इन विविध रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण को करने का कार्य विशेषकर हैदराबाद रियासत का भारत में विलय अत्यधिक दुष्कर और चुनौती-भरा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया।

देशी रियासतों के साथ जिन सहायक संधियों के आधार पर औपनिवेशिक शासन का संबंध था, उसकी देखभाल करने के लिए एक राजनीतिक विभाग था, जो वाइसराय की कार्यकारिणी के अन्तर्गत होता था। वर्ष 1946 में जब भारत की अन्तरिम सरकार का गठन हुआ तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन गृह

ISSN 2348-3857

मंत्रालय को सौंपा गया। गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था, अत: देशी रियासतों के मामले पटेल के अधीन ही आये। वाइसराय माउण्टबेटन ऐसी रियासतों के प्रकरण को स्वतंत्रता से पहले ही सुलझा लेना चाहते थे। अत: उन्होंने 15 अगस्त, 1947 से पूर्व ही 27 जून, 1947 को एक रियासती विभाग का गठन कर यह विभाग अन्तरिम सरकार के मंत्री सरदार पटेल के हवाले किया। पटेल ने इस विभाग के सचिव के रूप में वी.पी. मेनन की नियुक्ति करवाई, जो आई.सी.एस. अधिकारी नहीं थे अपितु क्लर्क के रूप में नियुक्ति पाकर उच्च स्थिति को प्राप्त किया था। पटेल और मेनन ने कूटनीतिक तरीकों से 15 अगस्त, 1947 से पूर्व ही अधिकांश रियासतों का भारत में विलय करवा लिया था। केवल जूनागढ़, जम्मू-कश्मीर और हैदराबाद रियासतों का विलय ही शेष था।

हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी, जो दक्कन के पठार में स्थित थी तथा चारों ओर से भारतीय भू-भाग से घिरी हुई थी। इसका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग मील से ज्यादा था और इसकी आबादी करीब 1 करोड़ 60 लाख थी। यहाँ पर आसफजाह वंश के निजाम मीर उस्मान अली का इस समय शासन था। इस रियासत की शुरूआत मुगलों के अधीनस्थ के रूप में वर्ष 1713 में हुई थी। हैदराबाद रियासत उत्तर में मध्य प्रान्त, पश्चिम में बम्बई और दक्षिण व पूर्व में मद्रास से घिरी हुई थी। इसकी आबादी में 85 प्रतिशत से अधिक हिन्दू थे, लेकिन सेना, पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों का दबदबा था। निजाम इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति एवं जिन्ना के सहायता के आश्वासन के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देख रहा था। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने इंग्लैण्ड के मशहूर वकील सर वाल्टर मोंक्टन को नियुक्त किया। इसी बीच भारत सरकार ने नवम्बर, 1947 में निजाम के साथ एक यथास्थिति सन्धि कर ली ताकि सन्धि वार्ता के आधार पर बात आगे बढ़ सके। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद के बीच जो संबंध थे, वे ब्रिटिश सरकार के उत्तराधिकारी के साथ भी जारी रहेंगे। इस समझौते से निजाम और भारत सरकार ने एक-दूसरे के क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि भी नियुक्त किये। भारत के प्रतिनिधि के रूप में के.एम. मुंशी को नियुक्त किया गया, जो पटेल के विश्वासपात्र थे। लेकिन निजाम दूसरी ही योजना पर काम कर रहा था। कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए निजाम सन्धि वार्ता को लम्बा खींचकर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा था। यहाँ तक कि अब हैदराबाद भारत को धमकी भी देने लगा था। जब माउण्टबेटन ने हैदराबाद को संविधान सभा में शामिल होने की सलाह दी तो उसके वकील मोंक्टन ने जवाब दिया कि अगर उनके मुवक्किल पर दबाव डाला गया तो वे वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान में शामिल होने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। निजाम ने हैदराबाद रियासत में भारत के हस्तक्षेप के मामले को यू.एन.ओ. में ले जाने का प्रयास भी किया। भारतीय सेना बार-बार हैदराबाद की सीमा का उल्लंघन करती है, ऐसी शिकायत लेकर लायक अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल यू.एन.ओ. भेजा गया। निजाम चाहता था कि उक्त प्रतिनिधि मण्डल के दिल्ली से न्यूयार्क जाने की व्यवस्था माउण्टबेटन करें। यह जानते ही पटेल ने कहा, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। उन्हें कह दीजिए कि दिल्ली हवाई अड्डे पर आपको उतरने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तब वह प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली के बदले कराची होकर न्यूयार्क पहुँचा था।

इसी बीच रियासत में तीन अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ हुई। पहली यह कि अधिकारियों की सांठगांठ से एक उग्रवादी मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन 'इत्तिहाद-उल-मुसलमीन' ताकतवर होता जा रहा था, जिसके नेता कासिम रजवी इसे और धार्मिक कट्टर बना रहा था। कासिम के नेतृत्व में इत्तिहाद ने 'रजाकार' नाम के एक अर्द्ध सैनिक संगठन को बढ़ावा दिया, जिसके सदस्य हैदराबाद की सड़कों पर तलवार और बंदुकों के साथ जुलूस निकालते थे। मार्च, 1948 तक रजाकारों की संख्या दस लाख पहुँच चुकी थी, जिसमें से एक लाख को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। रजाकारों के आतंक से हिन्दू प्रजा पलायन को मजबूर हो गई थी। रजाकारों ने निजाम की आजादी की घोषणा का समर्थन किया और इस बाबत् पर्चे छापकर लोगों में बांटे जिस पर लिखा था हैदराबादियों के लिए आजाद हैदराबाद और भारतीय संघ के साथ कोई समझौता नहीं। निजाम और रजाकारों को अपनी आजादी की मांग करने का उकसावा पाकिस्तान से भी मिला। जिन्ना ने कहा कि अगर कांग्रेस ने हैदराबाद पर कोई दबाव बनाया तो हिन्दुस्तान का एक-एक मुसलमान, जी हाँ पूरे देश के दस करोड़ मुसलमान एक होकर हिन्दुस्तान के इस पुराने राजवंश की रक्षा करेंगे। इन सबसे प्रेरणा लेकर रजवी कट्टर से क्रूर होता जा रहा था। उसने कहा, हमें हैदराबाद में ब्राह्मण और बनियों का शासन नहीं चाहिए। उसने आगे कहा जहाँ कहीं भी मुसलमानों का हित प्रभावित होता है, हमारी उससे सहानुभूति है। अगर नरक में भी मुसलमानों का हित प्रभावित होता है तो वहाँ भी हम मुसलमानों का साथ देंगे। इस तरह रजाकारों ने हैदराबाद के भारत विलय के सवाल को हिन्दु-मुस्लिम समस्या के रूप में रूपान्तरित किया।

दूसरी, अगस्त, 1947 को निजाम के जनवादीकरण की मांग को लेकर हैदराबाद रियासत की कांग्रेस ने एक सत्याग्रह आन्दोलन शुरू

कर दिया। करीब बीस हजार सत्याग्रही जेल में ठूंस दिए गए। उधर निजाम ने नवम्बर में मीर लायक अली को अपना नया दीवान बताया, जिसकी पाकिस्तान के प्रति स्पष्ट सहानुभूति थी। उसने अपने प्रशासन में हिन्दुओं को प्रतिनिधित्व देना चाहा, लेकिन कांग्रेस ने इसे बहुत देर से उठाया गया छोटा कदम बताकर खारिज कर दिया। तीसरी, वर्ष 1946 के मध्य से कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसान संघर्ष रियासत के नालगोण्डा, वारंगल, करीमनगर आदि तेलंगाना क्षेत्र में विकसित हुआ। उन्होंने जमींदारों से जमीन लेकर बांट दी तथा पूरे क्षेत्र से बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया। कई जगह उन्होंने अपनी समानान्तर सरकार बना ली थी।

उधर, इंग्लैण्ड की कंजरवेटिव पार्टी द्वारा भी निजाम की महत्वाकांक्षाओं को बल दिया जा रहा था। स्वयं मोक्टन कंजरवेटिव नेता थे, जिन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि वे हैदराबाद के निजाम के न्याय के लिए इस सवाल को विश्व जनमत के सामने उठाए। चर्चिल ने भी निजाम की पैरवी करते हुए कहा कि, ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि जिस राज्य को उन्होंने सार्वभौमिक राज्य के रूप में मान्यता दी है, उसे दबाया न जाये या उस पर हिंसा के बल पर कब्जा न किया जाए। पार्टी के बटलर ने चर्चिल का समर्थन करते हुए कहा कि, ब्रिटेन की सरकार को हैदराबाद की आजादी के न्यायपूर्ण दावे के लिए दबाव डालना चाहिए। उधर ऐसी खबरे भी आने लगी कि ब्रिटिश एजेण्टों द्वारा पाकिस्तान से हथियार और गोला-बारूद हवाई रास्ते से हैदराबाद पहुँचाए जा रहे है। पूर्वी यूरोप से भी हथियारों के आयात के समाचार आने लगे। इधर मद्रास के प्रधानमंत्री ने पटेल को लिखा कि हैदराबाद से आ रहे शरणार्थियों की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा है। के.एम. मुंशी ने भी निजाम के खिलाफ लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट पटेल को सौंपी। इन सबसे पटेल ने और इन्तजार करने के स्थान पर निर्णायक कार्यवाही करने का मानस बनाया। देहरादून में अपनी बीमारी के दौरान ही उन्होंने नेहरू को लिखा कि, मैं बहुत दृढ़ता से यह महसूस करता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब हमें उनको बिल्कुल साफ-साफ कह देना चाहिए कि हमें बिना शर्त विलय की स्वीकृति से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है।

जून, 1948 को लार्ड माउण्टबेटन ने गवर्नर-जनरल पद से इस्तीफा दे दिया। उधर पटेल देहरादून से वापिस दिल्ली आ गये थे। अब उनके लिए निर्णायक फैसला लेना आसान भी हो गया था और आवश्यक भी। तत्पश्चात् पटेल ने प्रस्तावित सैन्य कार्यवाही के लिए मंत्रिमण्डल की सहमति हेतु बैठक बुलाने का नेहरू से आग्रह किया। बैठक में वल्लभ भाई ने 13 सितम्बर, 1948 को तड़के हैदराबाद पर तीन ओर से सैन्य आक्रमण संबंधित योजना प्रस्तुत की। सेना के दक्षिण कमाण्डर जनरल राजेन्द्र सिंह ने सरदार को पहले ही सैन्य तैयारी के सन्दर्भ में आश्वस्त कर दिया था। लेकिन पण्डित नेहरू ने इस बैठक में कहा, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय इसे आक्रमण मानेगा। कश्मीर के मामले में हम उलझन में ही है। देश के मुसलमान निजाम के विरूद्ध उठाए गए इस कदम से नाराज होकर अशान्ति फैला देंगे। पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि, यदि इस समय हम यह कदम नहीं उठाएंगे तो हैदराबाद में हिन्दू आबादी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, हैदराबाद को पाकिस्तान का साथ है और दुनिया के मुस्लिम देश पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, इस प्रकार मुगल साम्राज्य को पीछे के द्वार से प्रवेश करने का आप अवसर देना चाहते है? इस परिस्थिति में यदि अपने पेट का यह फोड़ा निकालकर हम फेंक नहीं देंगे तो स्वयं अपनी कब्र खोदने का काम करेंगे। पटेल की बात से मंत्री मण्डल के सभी सदस्य सहमत थे लेकिन नेहरू तैयार नहीं हुए। उन्होंने गवर्नर जनरल राजाजी से आग्रह किया कि इस विषय पर ब्रिटिश सेनाध्यक्ष राय बुचर से भी सलाह ली जाये। बुचर ने कहा कि यह कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा, सरदार, मैंने अपनी नजरों से युद्ध देखा है। बम्बई, अहमदाबाद जैसे शहर नष्ट हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे। पटेल ने प्रतिप्रश्न किया, जनरल, ऐसी बम वर्षा हिटलर ने लन्दन पर कितने साल की थी? बुचर ने कहा, लगभग तीन-चार साल। पटेल का जवाब था, और फिर भी इन तीन-चार साल तक ब्रिटिश प्रजा ने उसका सामना किया। जो काम ब्रिटिश प्रजा तीन-चार साल तक कर सकी, वह काम कुछ दिनों के लिए भारतीय प्रजा क्यों नहीं कर सकती?

सितम्बर, 1948 की 12 तारीख की मध्य रात्रि को सेना ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली थी। 13 सितम्बर को तड़के भारतीय सेना ने नियत समय पर एक साथ तीन ओर से हमला आरम्भ किया। इस हमले को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। निजाम के सैनिक एक-दो दिन में ही मोर्चा छोड़कर भागने लगे। रजाकारों ने भी चार दिनों में ही समर्पण कर दिया। इस लड़ाई में भारतीय सेना के बयालिस जबकि दो हजार रजाकार मारे गये। 17 सितम्बर को निजाम ने हैदराबाद रियासत का भारत में विलय स्वीकार कर रेडियो पर अपनी प्रजा को सलाह दी कि वे शेष भारत के लोगों के साथ शान्तिपूर्ण और भाईचारे के साथ रहे। विलय पत्र हस्ताक्षर करवाने जब पटेल हैदराबाद हवाई अड्डे पहुँचे तब निजाम उनके स्वागत को एयरपोर्ट पर थे, यह दुर्लभ अवसर था। पटेल ने कहा निजाम समाप्त हो गया है। भारत के सीने का कैंसर हमने मिटा दिया है।

भारत की सरकार ने निजाम को माफ करते हुए उसे हैदराबाद सूबे के राजप्रमुख के रूप में नियुक्ति प्रदान की। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारत में विलीनीकरण हो गया।

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर जान स्ट्रेची ने अपनी पुस्तक इण्डिया में लिखा कि, भारतीय राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है, न ही भविष्य में ऐसा होने की कोई सम्भावना है। हिन्दुस्तान बस एक सुविधाजनक नाम मात्र है, जिसमें कई सारे राष्ट्र एक साथ रह रहे थे। स्ट्रेची के अनुसार यूरोप के देशों में आपसी फर्क जितना नहीं था, उससे ज्यादा फर्क भारत के इलाकों के बीच था। उनसे कहा, पंजाब और बंगाल की तुलना में स्कॉटलैण्ड व स्पेन ज्यादा नजदीक है। पटेल की राष्ट्र के एकीकरण और आधुनिक राष्ट्र के विकास में भूमिका स्ट्रेची को उपयुक्त उत्तर था, जब भाषा, क्षेत्र, धर्म आदि ऊपरी भेदों को मिटाकर राष्ट्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। हैदराबाद का विलय उसी राष्ट्रीय यज्ञ में पटेल की महत्वपूर्ण आहूति थी, जिसे यह कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा और यह अस्वाभाविक नहीं है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग इस पूरे प्रकरण में नेहरू और पटेल की भूमिका की तुलना भी करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मुंशी, के.एम., द एण्ड ऑफ एन एरा, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1957
2. तीर्थ, रामानन्द, मेमॉयर्स ऑफ हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1967
3. गोपाल, एस., जवाहर लाल नेहरू : ए बायोग्राफी, केप पब्लिशर्स, लन्दन, 1979
4. गाँधी, राजमोहन, पटेल : ए लाइफ, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1990
5. मेनन, वी.पी., इन्टिग्रेशन ऑफ द इण्डियन स्टेट्स, पुर्नमुद्रित, ओरिएण्ट लौंगमेन, 1997
6. चन्द्र, मुखर्जी एवं मुखर्जी, आजादी के बाद का भारत : 1947-2000, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशायल, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2002
7. गुहा, रामचन्द्र, भारत गांधी के बाद, पेंगुइन बुक्स, गुड़गांव, 2014
8. जोशी, दिनकर, महामानव सरदार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014